



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2014/चैत्र 3, 1936

No. 83]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2014/CHAITRA 3, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2014

**विषय :** चीन थाइलैंड और वियतनाम के मूल के या वहां से निर्यातित पोलिएस्टर के “सभी पूर्णतः ड्रॉन या पूर्णतः ओरिएन्टेड यार्न/फ्लैट यार्न (नॉन टेक्सचर्ड और नॉन-पीओवाई)” और अन्य यार्नों के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

**फा. सं. 15/03/2014-डी जी ए डी :-** वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन थाइलैंड और वियतनाम के मूल के या वहां से निर्यातित पोलिएस्टर के “सभी पूर्णतः ड्रॉन या पूर्णतः ओरिएन्टेड यार्न/फ्लैट यार्न (नॉन टेक्सचर्ड और नॉन-पीओवाई)” और अन्य यार्नों (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । प्राधिकारी की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना 29 सितंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/3/2008-डीजीएडी के तहत प्रकाशित की गई थी । जांच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा 11 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 124/2009-सी.शु. के तहत संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था ।

यतः मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., मै. वेलनॉन पोलिएस्टर लि., मै. गार्डन सिल्क मिल्स लि. तथा मै. आलोक इंडस्ट्रीज लि. (जिन्हें आगे “घरेलू उद्योग” कहा गया है) ने चीन थाइलैंड और वियतनाम के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और चीन थाइलैंड और वियतनाम के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने, बढ़ाने और उसकी राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ।

## घरेलू उद्योग

1. निर्णायक समीक्षा हेतु यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., मै. वेलनॉन पोलिएस्टर लि., मै. गार्डन सिल्क मिल्स लि. तथा मै. आलोक इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है । दो गैर आवेदक उत्पादकों अर्थात् जेबीएफ इंडस्ट्रीज लि. और सुमीत इंडस्ट्रीज लि. ने आवेदन का समर्थन किया है । आवेदक उत्पादकों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन में 52 प्रतिशत बनता है और इसलिए ये नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं ।

## विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, पोलिएस्टर के सभी पूर्णतः ड्रॉन या पूर्णतः ओरिएन्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न (नॉन टेक्सचर्ड और नॉन-पीओवाई) और अन्य यार्न जो सीमाशुल्क शीर्ष 5402.47 के टैरिफ विवरण के अनुरूप हैं (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) इस उत्पाद को वाणिज्यिक बाजार शब्दावली में सामान्यतः “पूर्णतः ड्रॉन यार्न” (एफडीवाई) कहा जाता है । संबद्ध वस्तु का प्रयोग परिधान/घरेलू वस्त्र, और अन्य औद्योगिक वस्त्रों के विनिर्माण में होता है । संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशन उनके डेनियर्स, तन्थता, लस्टर्स, रंगों (जैसे सेमीडल, ब्राइट, सुपर ब्राइट, फुल डल, डोप डाइड), कॉस सेक्शन और सिकुड़ने की दृष्टि से परिभाषित किए जाते हैं ।

3. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 और पुनः सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुसार 5402.47 के अंतर्गत “मानव निर्मित फिलामेंट” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में

बाध्यकारी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जिस संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है, वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समानरूप है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को चीन थाइलैंड और वियतनाम से पाटित वस्तु के “समान वस्तु” है। पाटित वस्तु और याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। और इस प्रकार इन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तुएं” माना जाना चाहिए। वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

#### शामिल देश

4. यह याचिका चीन जन गण, थाइलैंड और वियतनाम से संबद्ध उत्पाद के पाटन के बारे में दायर की गई है। यह नोट किया जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान वियतनाम से कोई आयात नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने भी अन्य देशों के लिए वियतनाम से कीमतों का उल्लेख करते हुए कोई आंकड़ा या साक्ष्य उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अतः वियतनाम को बाहर रखा गया है। तदनुसार वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन और थाइलैंड हैं और इनका उपयोग आगे संबद्ध देशों के रूप में भी किया गया है।

#### जांच की अवधि

5. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2012 से 30 सितंबर, 2013 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 और जांच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

#### निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

6. दायर किए गए विधिवत पुष्टीकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

#### प्रक्रिया

7. इस समीक्षा में 29 सितंबर, 2009 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं० 14/03/2008—डीजीएडी के तहत मूल जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल हैं।

8. इस समीक्षा में उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

#### सूचना प्रस्तुत करना

9. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश(शों) की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य विभाग,  
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली

10. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।

#### समय सीमा

11. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिन के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) के बारे में सूचित करें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

#### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

13. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

14. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।
16. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।
17. प्रस्तुत की गई सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है या वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
18. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में बेहतर कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत इसका प्रकटन ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को नहीं करेंगे।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

19. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### असहयोग

20. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

#### (DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### INITIATION NOTIFICATION (SUNSET REVIEW)

New Delhi, the 24th March, 2014

**Subject: Initiation of Sunset Review (SSR) Investigation in respect of imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns originating in or exported from China, Thailand and Vietnam.**

**F. No. 15/03/2014-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns (hereinafter also referred as subject goods) from China, Thailand and Vietnam. The final findings notification of the Authority was published vide Notification No. 14/03/2008-DGAD dated the 29th September, 2009. On the basis of the findings, anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject countries were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 124/2009-Customs dated 11th November, 2009.

Whereas, M/s Reliance Industries Ltd., M/s Wellknown Polyesters Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd. and M/s Alok Industries Ltd. (hereinafter referred to as "domestic industry") have filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China, Thailand and Vietnam, and consequent injury and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from China, Thailand and Vietnam.

**Domestic Industry**

1. The application for the sunset review has been filed by M/s. Reliance Industries Ltd., M/s Wellknown Polyesters Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd. and M/s Alok Industries Ltd. on behalf of the domestic industry. Two of the non-applicant producers namely JBF Industries Ltd. and Sumeet Industries Ltd. are also supporting this application. The applicant Producers accounts for 52% share in the total domestic production and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

**Product under Consideration and Like Article**

2. The product under consideration in the present application, as defined in the original investigation, is All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of Customs Heading 5402.47 (hereinafter also being referred to as “subject goods”). The product in commercial market parlance is generally known as “Fully Drawn Yarn” (FDY). The subject goods are used for manufacture of apparel/household textiles, and other industrial textiles. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage.

3. The product under consideration is classified under the category “Man made filaments” in Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 5402.47 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. Petitioners have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. Hence, the goods produced by the domestic industry are ‘Like Article’ to dumped goods from China, Thailand and Vietnam. There is no difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the petitioners. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like articles’ under the Anti Dumping Rules. The subject goods produced by the petitioner is being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

**Countries involved**

4. The present petition is filed in respect of the dumping of the product concerned from China PR, Thailand and Vietnam. It is noted that there have been no imports from Vietnam during the entire injury period. The Domestic Industry has also expressed its inability to provide any data or evidence indicating the prices from Vietnam to other countries. Therefore Vietnam has been excluded. Accordingly, the countries involved in the present Sunset Review investigation are China and Thailand and are also referred as subject countries hereinafter.

**Period of Investigation**

5. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October, 2012 to 30th September, 2013 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April, 2010 to March, 2011, April 2011 to March, 2012, April 2012 to March, 2013 and the period of investigation (POI) has been considered.

**Initiation of Sunset Review**

6. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of anti-dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**Procedure**

7. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation *vide* final findings Notification No. 14/03/2008-DGAD, dated 29th September, 2009.

8. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules *supra* shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

**Submission of Information**

9. The known exporters in the subject countries, the government of the subject country(ies) through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :

Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Department of Commerce  
Room No. 240, Udyog Bhawan,  
New Delhi.

10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**Time Limit**

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

12. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

**Submission of information on confidential basis**

13. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

14. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

15. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

16. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

17. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

18. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

19. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

20. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority